concessional rates for soft cover edition and text books. The newsprint quota, should also be revised at the same time I request the Government to enforce the provisions of the 1974 Paper control Order Strictly.

(vii) Need for a direct Air India Flight from Trivandrum to Doha and Muscat.

Prof P.J. Kurien (Mavelikara) : The Indians residing in Doha and Muscat have sent in a number of representations to Government of India demanding direct flights from Doha and Muscat to Trivandrum, Nearly a lakh of Indians, mostly Keralites. are residing in these two places and they face a lot of difficulties for want of direct flights. They are now coming to Kerala *Via* Bombay Airport where they are put to much inconvenience and harassment. On a number of occasions I have seen Keralites coming from these countries in Bombay Airport and staying for days together for getting a seat in Cochin flight. Most of them come with OK ticket from abroad, only to be told by I.A. officials that they are in the waiting list and finally they are forced to stay in Bombay wasting their precious holidays and spending a lot of money and putting up with much difficulties. The only solution to the problem is direct flight to Trivandrum from Doha and Muscat. Air India is in favour of commercing these flights. Hon. Minister had given assurance more than once in this House that steps will be taken to start these flights. But so far the assurance has not materialised.

I urge upon the Minister for civil Aviation to take immediate steps to start Doha-Trivandrum and Muscat-Trivandrum flights.

(viii) Demand for circular/Ring Road transport service in Bangalore City.

Shri T.R. Shamanna (Bangalore South) : Bangalore city has grown abnormally in recent year both in size and population. In 1971 the population of the the city was 16 lakhs and in 1981 it has shot up to nearly 30 Lakhs. Within 20 years the city which was 40 sq. miles is now nearing 80 sq. miles. This rapidly growing city is facing inadequate transport facilities. The city's growth is to a great extent "horizontal" (it is about 20 Km. east to west and north to south is 18 Km). Though there are monpolized bus services (B.T.S.) and many two and three-wheeler vehicles, the transport facility is rather very inadequate. Many newly formed layouts and undeveloped areas have no means of transport. More than 5 lakhs of students, factory-workers, office going commuters have to move about from their houses to their working spots. Delhi has nearly 3,500 buses but Bangalore has only about 600 buses. The bus will be generally overcrowded and there will be long queues in bus-stops. Thousands of people come every day from roundabout villages and from other parts of the State.

On account of water scarcity and lack of other civic needs, there is an urge for developing satellite towns.

Year after the problem of traffic needs is going from bad to worse. There is a strong urge to have circular or ring rail service to meet the increasing traffic needs of the city.

Want of adequate finance is the usual excuse put forth to take up the programme to give a ring rail to Bangalore city.

Delhi being the capital city of Central Government, it has got an electric train project which will be shortly put into Service. It is of utmost necessity that steps should be taken to start the project for a ring road to Bangalore in order to meet the transport of this growing city. Further, the open space available round the city is being used for building houses and factories. If it is delayed, the cost of acquiring land will be more. The Government of Karnataka and the city corporation and Bangalore Development Authority have agreed to give land and also bear a major share of finance.

I request the Railway Minister and Planning Commission to take this important project without further delay.

(ix) Alleged eviction of tribals by forest department in Madhya Pradesh.

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) :—उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में विशेष रूप से छिंदवाड़ा, मंडला आदि के हजारों आदिवासी परिवार विगत 25-30 वर्षों से वन विभाग की भूमि पर काश्तकारी कर अपने परिवारों का पालन पोषण करते आ रहे हैं । मध्य प्रदेश वन अधिकारी इस वर्ष खेतों की खड़ी फसल काट कर नष्ट कर रहे हैं । उन आदिवासी कृषकों के साथ मार पीट तथा अत्याचारों की घटनायें भी बढ़ती जा रही है : फोरेस्ट अधिकारियों ने यह बताया की केन्द्र सरकार के आदेश हैं कि वन-भूमि पर काश्तकारी करने वालों को शक्ति के बल पर बेदखल किया जाये । पुलिस द्वारा गिरफतार किया जावें तथा अदालतों में मुकदमें चलाए जायें । इसी आदेश के अनुसार कब्जाधारी आदिवासी किसानों से जमीनें छीनी जा रही है ।

मध्य प्रदेश वन अधिकारियों द्वारा विगत 25-30 वर्षों से इन आदिवासियों से मुआवजे तथा जुर्माने के रूप में बहुत बड़ी राशि वसूल की गई है ।

इसलिए केन्द्र शासन से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा केन्द्र शासन के नाम पर जो अदिवासियों के साथ अत्याचार तथा जमीन से बेदखली की जा रही है उस पर तुरन्त रोक लगाई जायें तथा पूरे प्रकरण के जांच के आदेश पारित किए जायें ।

(x) Relief measures for brought effected tribals of Santhal Parganas in Bihar

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) :—उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

संथाल परगना में भूख से मरने का सिलसिला प्रारंभ —

लगातार तीन साल से सूखे से पीड़ित बिहार के संथाल परगना जिले में भूख से मरना शुरू हो गया है । जामताड़ा अनुमंडल के नाला थानान्तर्गत जीवनपुर गांव में एक आदिवासी किसान 28 जुलाई को भूख उसे उतड़प-तड़प कर मर गया ।

संपूर्ण जिला भयंकर अकाल की उस्थिति से होकर गुजर रहा है । स्वयं जिले के उपायुक्त ने भी स्वीकार किया है कि संपूर्ण गोड्डा और जामताड़ा अनुमंडल अकाल की चपेट में हैं । दुमका अनुमंडल के लिट्टी पाड़ा गांव में पहाड़ी आदि वासी पहाड़ों से उत्तर उत्तर कर घर-घर माड़ मागने जाते हैं, लेकिन उन्हें माड़ भी नहीं मिलता ।

बड़े-बूढ़े लोगों का कहना है कि जिले में पिछले साठ वर्षों से ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा । अगर सरकार की ओर से किसी तरह का राहत कार्य नहीं चलाया गया तो भूख से मरने वालों की संख्या में वद्धि होने की आंशका है ।

अकाल पीड़ित दर्जनों ग्रामों का भ्रमण करने के बाद बतयालया गया है कि 50 प्रतिशत से अधिक धान के बिचड़े रोपने के पहले ही सरकार जल चुके हैं । सेर्षा के अभाव के अधिकाश ग्रामों में रोपनी शुरू भी नहीं की जा सकी है । कुछ ग्रामों की एक से पांच प्रतिशत जमीन में किसी प्रकार रोपनी संभव हो सकी है । खेत मजदूरों को कहीं काम नहीं मिल रहा है जिसके कारण वे भयंकर भुखमरी के कगार पर हैं । अगर तुरन्त राहत कार्य शुरू नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर लोग भुखमरी के शिकार होंगे ।

यह भी कहा जाता है कि जामताड़ा में 60 प्रतिशत से भी अधिक धान के बिचड़े जल चुके हैं । उनका कहना है कि जामताड़ा के दर्जनों ग्रामों में धान की रोपनी शुरू भी नहीं हों सकी है । इस प्रकार संपुर्ण जिला अकाल के मुंह में समा चुका है ।

अतः ऐसी प्राकृतिक विपत्ति के समय सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि वह अकाल पीड़ित